आयकर विभाग को सीतारमण के सात मंत्र

रिफंड प्रक्रिया और तेज करने पर जोर, स्वैच्छिक कर अनुपालन बढ़ाने की अपील

नई दिल्ली, 26 जुलाई. वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने 167वें आयकर दिवस के अवसर पर आयकर विभाग के लिए सात व्यापक सिद्धांत सुझाते हुए करदाताओं का विश्वास मजबूत करने, स्वैच्छिक कर अनुपालन को बढ़ावा देने और तकनीक के जिम्मेदार उपयोग पर विशेष जोर दिया.

उन्होंने कहा कि आयकर विभाग की भूमिका अब केवल कर संग्रह तक सीमित नहीं है, बल्कि निष्पक्ष, पारदर्शी और करदाता-केंद्रित व्यवस्था विकसित करना भी उसकी प्रमुख जिम्मेदारी है. साथ ही उन्होंने विभाग को आयकर रिफंड की प्रक्रिया और तेज करने तथा शिकायतों के त्वरित निस्तारण पर लगातार काम करने की सलाह दी.नई दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोजित 167वें आयकर दिवस समारोह को संबोधित करते हुए वित्त मंत्री ने कहा कि आयकर विभाग को स्वैच्छिक कर अनुपालन को मजबूत करना, करदाताओं के अनुभव को सरल और सहज बनाना, कर संबंधी निश्चितता बढ़ाना, तकनीक का जिम्मेदारीपूर्वक उपयोग करना, संस्थागत उत्कृष्टता विकसित करना, जनता का विश्वास मजबूत करना और निरंतर सुधार की संस्कृति अपनाना.

इन सात सिद्धांतों को अपने कार्य का आधार बनाना चाहिए. उन्होंने कहा कि ये सभी प्राथमिकताएं एक-दूसरे की पूरक हैं और विकसित भारत-2047 के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगी.

> सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग अब केवल राजस्व संग्रह करने वाली संस्था नहीं रहा, बल्कि व्यापार सुगमता बढ़ाने, करदाताओं को बेहतर सेवाएं देने और सरकार तथा नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने का प्रमुख माध्यम बन चुका है. उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम-2025लागू होने के बाद कानून को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया गया है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हुआ है और अनिश्चितता कम हुई है वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है.

नेपाल में भारतीय नोटों पर राहत

काठमांडू, 26 जुलाई . भारत और नेपाल के बीच व्यापार, पर्यटन और लोगों की आवाजाही को आसान बनाने की दिशा में नेपाल सरकार ने बड़ा फैसला लिया है. नेपाल राष्ट्र बैंक (एनआरबी) ने भारतीय मुद्रा के आवागमन पर लगी पाबंदियों में आंशिक ढील देते हुए भारतीय और नेपाली नागरिकों को 9 नवंबर 2016 के बाद जारी 200 और 500 रुपये के नए भारतीय नोट अपने साथ लाने और ले जाने की अनुमति दे दी है. नए नियम के तहत कोई भी भारतीय या नेपाली नागरिक अधिकतम 25 हजार रुपये तक की भारतीय मुद्रा अपने साथ नेपाल ला या वहां से ले जा सकेगा. नेपाल राष्ट्र बैंक के अनुसार, यह अनुमति केवल नए डिजाइन वाले 200 और 500 रुपये के नोटों पर लागू होगी.

अगस्त में 14 दिन बंद रहेंगे बैंक

सात दिन क्षेत्रीय अवकाश के कारण बैंक बंद

ऑनलाइन बैंकिंग और एटीएम सेवाएं रहेंगी जारी

नई दिल्ली, 26 जुलाई. अगर अगस्त महीने में आपको बैंक से जुड़ा कोई महत्वपूर्ण काम निपटाना है, तो पहले छुट्टियों का कैलेंडर जरूर देख लें. भारतीय रिजर्व बैंक (आरबीआई) के अवकाश कैलेंडर के अनुसार, अगस्त 2026 में देशभर के विभिन्न राज्यों में कुल 14 दिन बैंक बंद रहेंगे. इनमें पांच रविवार, दूसरा और चौथा शनिवार तथा विभिन्न राज्यों के स्थानीय त्योहारों और विशेष अवसरों के कारण सात अतिरिक्त अवकाश शामिल हैं.

हालांकि, ये सभी छुट्टियां पूरे देश में एक साथ लागू नहीं होंगी.

कई अवकाश केवल संबंधित राज्यों और शहरों के बैंकों पर ही लागू होंगे.देशभर में 8 अगस्त को महीने का दूसरा शनिवार और 22 अगस्त को चौथा शनिवार होने के कारण सभी सरकारी और निजी बैंक बंद रहेंगे.

इसके अलावा 2, 9, 16, 23 और 30 अगस्त को रविवार होने से भी बैंकिंग सेवाएं शाखाओं में उपलब्ध नहीं रहेंगी.इसके अतिरिक्त, स्वतंत्रता दिवस, रक्षाबंधन, जन्माष्टमी, गणेश चतुर्थी और अन्य स्थानीय पर्वों के अवसर पर अलग-अलग राज्यों में बैंकों की छुट्टियां रहेंगी. इसलिए ग्राहकों को सलाह दी गई है कि वे अपने शहर या राज्य के बैंक अवकाश की जानकारी पहले से जांच लें और उसी के अनुसार अपने जरूरी कार्यों की योजना बनाएं.

> बैंक शाखाएं बंद रहने के बावजूद ग्राहकों को डिजिटल सेवाओं में किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी. इंटरनेट बैंकिंग, मोबाइल बैंकिंग, यूपीआई, एटीएम, नकद निकासी, फंड ट्रांसफर और ऑनलाइन भुगतान जैसी सुविधाएं सामान्य रूप से उपलब्ध रहेंगी. इन सेवाओं का उपयोग कर ग्राहक अधिकांश बैंकिंग कार्य घर बैठे ही पूरा कर सकते हैं.बैंकिंग विशेषज्ञों का कहना है कि चेक जमा करने, डिमांड ड्राफ्ट बनवाने, खाते से जुड़े दस्तावेजों का सत्यापन, लॉकर संचालन या अन्य शाखा-आधारित सेवाओं के लिए ग्राहकों को छुट्टियों से पहले ही बैंक पहुंच जाना चाहिए.

आयकर रिटर्न भरने का दूसरा मौका

48 महीने तक अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल करने की सुविधा

छूटी हुई आय घोषित कर टैक्स जमा करने का दूसरा अवसर

नई दिल्ली, 26 जुलाई. आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तारीख अब नजदीक है. आकलन वर्ष 2026-27 के लिए बिना विलंब शुल्क के आयकर रिटर्न दाखिल करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई 2026 निर्धारित है. ऐसे में जिन करदाताओं ने अभी तक अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं किया है, उन्हें समय रहते यह प्रक्रिया पूरी कर लेनी चाहिए. वहीं, जो लोग पिछले वर्ष किसी कारणवश अपना आयकर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए थे, उनके लिए भी राहत की खबर है.

आयकर विभाग की अपडेटेड आयकर रिटर्न सुविधा के माध्यम से अब भी पुराना रिटर्न दाखिल किया जा सकता है.अपडेटेड आयकर रिटर्न (आईटीआर-यू) आयकर विभाग द्वारा करदाताओं को दिया गया एक विशेष अवसर है. यह सुविधा आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 139(8ए) के तहत उपलब्ध कराई गई है.

इसका उद्देश्य उन करदाताओं को अपनी गलती सुधारने का अवसर देना है, जो समय पर रिटर्न दाखिल नहीं कर पाए या जिन्होंने अपनी मूल रिटर्न में किसी आय का उल्लेख नहीं किया था. इस व्यवस्था के तहत करदाता अपनी छूटी हुई या अतिरिक्त आय घोषित कर उस पर देय कर तथा निर्धारित अतिरिक्त राशि का भुगतान कर सकते हैं.यदि कोई करदाता सामान्य रिटर्न, विलंबित रिटर्न या संशोधित रिटर्न दाखिल करने की समय-सीमा चूक गया है, तब भी वह अपडेटेड आयकर रिटर्न दाखिल कर सकता है.

> सीतारमण ने कहा कि आयकर विभाग अब केवल राजस्व संग्रह करने वाली संस्था नहीं रहा, बल्कि व्यापार सुगमता बढ़ाने, करदाताओं को बेहतर सेवाएं देने और सरकार तथा नागरिकों के बीच विश्वास कायम करने का प्रमुख माध्यम बन चुका है. उन्होंने कहा कि आयकर अधिनियम-2025लागू होने के बाद कानून को अधिक सरल और व्यवस्थित बनाया गया है, जिससे करदाताओं के लिए अनुपालन आसान हुआ है और अनिश्चितता कम हुई है वित्त मंत्री ने बताया कि आयकर विभाग के ई-फाइलिंग पोर्टल की क्षमता में भी उल्लेखनीय सुधार किया गया है.

सेंसेक्स एक सप्ताह में 2,091 अंक टूटा

निवेशकों की नजर एक बार फिर पश्चिम एशिया की स्थिति पर होगी

मुंबई, 26 जुलाई पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने के कारण बीते सप्ताह घरेलू शेयर बाजारों में बड़ी गिरावट देखी गयी और बीएसई का सेंसेक्स पांच दिन में 2,091 अंक फिसल गया. अब आने वाले सप्ताह में निवेशकों की नजर एक बार फिर पश्चिम एशिया की स्थिति पर होगी.

पश्चिम एशिया में तनाव बढ़ने से लंदन का ब्रेंट क्रूड वायदा एक बार फिर 100 डॉलर प्रति बैरल तक पहुंच गया. इससे भारत जैसे ऊर्जा आयातक देश में घरेलू शेयर बाजारों में पांचों दिन बिकावाली देखी गयी. आने वाले सप्ताह में अमेरिका-ईरान के बीच तनाव के अलावा निवेशकों की नजर कंपनियों के तिमाही परिणामों और अमेरिकी फेडरल रिजर्व की बैठक पर भी रहेगी. अगले सप्ताह बीईएल, केनरा बैंक, कोल इंडिया, हिंदुस्तान यूनीलिवर, एलएंडटी और एशियन पेंट्स के साथ कई कंपनियों के तिमाही परिणाम जारी होने हैं.गत सप्ताह बीएसई का 30 शेयरों वाला सेंसेक्स 2,091.68 अंक (2.68 प्रतिशत) की साप्ताहिक गिरावट में रहा. सप्ताहांत पर शुक्रवार को यह 76,059.77 अंक पर बंद हुआ जो 12 जून के बाद का इसका निचला स्तर है.नेशनल स्टॉक एक्सचेंज का निफ्टी-50 सूचकांक भी सप्ताह के दौरान 566.85 अंक यानी 2.33 प्रतिशत गिरकर 12 जून के बाद के निचले स्तर 23,767.45 अंक पर बंद हुआ.

> वृहत बाजार में निफ्टी मिडकैप-50 सूचकांक 1.23 प्रतिशत और स्मॉलकैप-100 सूचकांक 2.18 प्रतिशत टूट गया.बीते सप्ताह सेंसेक्स की 30 में से 20 कंपनियों के शेयर लाल निशान में रहे. एचडीएफसी बैंक में सबसे अधिक 9.40 प्रतिशत की गिरावट रही.एक्सिस बैंक का शेयर 7.59 प्रतिशत, इंफोसिस का 5.11, इंडिगो का 5.02, बजाज फाइनेंस का 4.08, अडानी पोर्ट्स का 3.76, रिलायंस इंडस्ट्रीज का 3.64, भारतीय स्टेट बैंक का 2.78 और मारुति सुजुकी का 2.51 प्रतिशत टूट गया. सप्ताह के दौरान इटरनल का शेयर 2.34 फीसदी, एशियन पेंट्स का 1.89 प्रतिशत, टाटा स्टील का 1.72, कोटक महिंद्रा बैंक का 1.32 और बीईएल का 1.06 प्रतिशत नीचे बंद हुआ. एलएंडटी ने 0.78 प्रतिशत, टेक महिंद्रा ने 0.65, टीसीएस ने 0.63, आईसीआईसीआई बैंक ने 0.61प्रतिशत का नुकसान उठाया.

अगस्त में आएंगे 12 से ज्यादा आईपीओ

मुंबई, 26 जुलाई. अगस्त का महीना कई बड़े अवसर लेकर आने वाला है. बाजार में सकारात्मक माहौल और निवेशकों की मजबूत भागीदारी के बीच 12 से अधिक कंपनियां प्रारंभिक सार्वजनिक निर्गम (आईपीओ) लाने की तैयारी में हैं. इनमें जेप्टो, ट्रूहॉम फाइनेंस, शिपरॉकेट, एलिवेट कैंपसेज और मिल्की मिस्ट डेयरी फूड जैसी प्रमुख कंपनियां शामिल हैं. इन सभी प्रस्तावित आईपीओ के माध्यम से कंपनियां 25 हजार करोड़ रुपये से अधिक की पूंजी जुटाने का लक्ष्य लेकर बाजार में उतर सकती हैं. सबसे अधिक चर्चा क्विक कॉमर्स कंपनी जेप्टो के आईपीओ की है. कंपनी 8,010 करोड़ रुपये के नए शेयर जारी करेगी.

45% भारतीय निर्यात शुल्क से बाहर

नयी दिल्ली, 26जुलाई सरकार ने कहा है कि अमेरिका द्वारा भारतीय उत्पादों पर 23 जुलाई को घोषित 10 प्रतिशत अतिरिक्त शुल्क के दायरे से देश के 45 प्रतिशत निर्यात बाहर हैं और 55 प्रतिशत निर्यात ही इससे प्रभावित होंगे.

अमेरिका के वाणिज्य दूत (यूएसटीआर) ने 23 जुलाई को अमेरिकी व्यापार अधिनियम, 1974 के तहत भारत सहित 60 अर्थव्यवस्थाओं के खिलाफ अतिरिक्त शुल्क लगाने की घोषणा की थी. यह शुल्क उन उत्पादों के अमेरिका में आयात को हतोत्साहित करने के लिए लगाया गया है जिसमें उत्पाद के निर्माण में बेगार का इस्तेमाल हुआ है.

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय ने शनिवार को बताया कि अमेरिका को होने वाले निर्यात का एक बड़ा हिस्सा, जिस पर वर्तमान में कोई अतिरिक्त शुल्क नहीं लगता - जैसे जेनेरिक दवाइयां, स्मार्टफोन और कुछ अन्य निर्दिष्ट उत्पाद - अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क के दायरे से बाहर रहेगा. इसके अलावा, अमेरिकी व्यापार अधिनियम की धारा 232 के तहत पहले से शामिल उत्पाद, जैसे इस्पात, एल्यूमिनियम और ऑटो पार्ट्स भी इस अतिरिक्त 10 प्रतिशत शुल्क के अधीन नहीं होंगे.

उल्लेखनीय है कि धारा 232 के तहत लगाये गये शुल्क सीमित अपवादों को छोड़कर लगभग सभी देशों पर समान रूप से लागू होते हैं.

महानदी बेसिन में गहरे समुद्र की ड्रिलिंग शुरू

नई दिल्ली, 26 जुलाई. भारत की ऊर्जा सुरक्षा को मजबूत करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाते हुए केंद्रीय पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने शनिवार को महानदी अपतटीय बेसिन में पहले मूल्यांकन कुएं एमएन-डीडब्ल्यूएन18-1-एचडी की ड्रिलिंग की शुरुआत की. इसे भारत के गहरे समुद्री तेल एवं गैस अन्वेषण अभियान में एक नए अध्याय की शुरुआत माना जा रहा है. यह कुआं प्रस्तावित चार गहरे समुद्री मूल्यांकन कुओं में पहला है, जिनके माध्यम से देश के सबसे संभावनाशील अपतटीय क्षेत्रों में हाइड्रोकार्बन संसाधनों का वैज्ञानिक आकलन किया जाएगा.

10 लाख के लोन से बदली तकदीर

15 साल में पढ़ाई छोड़ शुरू की मजदूरी

सरकारी ऋण से खड़ा किया मशीन उद्योग

छपरा (बिहार), 26 जुलाई कहते हैं कि कठिन परिस्थितियां इंसान को या तो तोड़ देती हैं या फिर उसे नई ऊंचाइयों तक पहुंचा देती हैं. बिहार के सारण जिले के गरखा प्रखंड के बीबीपुर गांव निवासी इमाम अली ने दूसरी राह चुनी. महज 15 वर्ष की उम्र में परिवार की आर्थिक तंगी के कारण पढ़ाई छोड़कर मजदूरी करने निकले इमाम आज एक सफल उद्यमी के रूप में पहचान बना चुके हैं.

कोरोना महामारी के दौरान नौकरी छूटने के बाद उन्होंने हार मानने के बजाय सरकारी योजना के तहत 10 लाख रुपये का ऋण लेकर मशीन निर्माण का अपना उद्योग शुरू किया. आज उनकी फैक्ट्री में खाद्य प्रसंस्करण से जुड़ी कई प्रकार की मशीनें तैयार होती हैं और 10 से अधिक लोगों को रोजगार भी मिल रहा है.इमाम अली का परिवार खेती-किसानी पर निर्भर था. उनके पिता छोटे किसान थे और सीमित आय में पूरे परिवार का पालन-पोषण करते थे. घर की आर्थिक स्थिति कमजोर होने के कारण इमाम ने कम उम्र में ही परिवार की जिम्मेदारी उठाने का फैसला किया.

10 से अधिक लोगों को मिला रोजगार

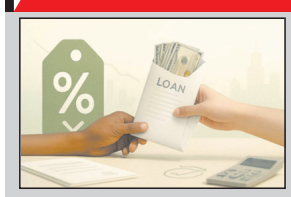

इमाम अली का मानना है कि सरकारी योजनाओं का सही उपयोग कर युवा आत्मनिर्भर बन सकते हैं. उन्होंने बताया कि उनका उद्देश्य केवल अपना व्यवसाय बढ़ाना नहीं, बल्कि अधिक से अधिक लोगों को रोजगार उपलब्ध कराना भी है .आज उनकी फैक्ट्री में 10 से अधिक लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार मिला हुआ है. उनके बनाए उपकरणों के माध्यम से कई अन्य लोग भी अपना छोटा व्यवसाय शुरू कर रहे हैं. एक समय मजदूरी करने वाले इमाम अली आज छपरा के सफल उद्यमियों में गिने जाते हैं. उनकी संघर्ष, मेहनत और आत्मविश्वास की कहानी उन युवाओं के लिए प्रेरणा है, जो सीमित संसाधनों के बावजूद अपने सपनों को साकार करने का साहस रखते हैं.

राजधानी में सजी वीव्स ऑफ इंडिया

नई दिल्ली, 26 जुलाई. राजधानी में जनपथ स्थित सेंट्रल कॉटेज इंडस्ट्रीज़ एम्पोरियम (सीसीआईई) में 'वीव्स ऑफ इंडिया' महोत्सव का शुक्रवार को शुभारंभ हुआ. केंद्रीय वस्त्र मंत्रालय के अंतर्गत विकास आयुक्त (हथकरघा) कार्यालय द्वारा आयोजित यह महोत्सव 24 जुलाई से 7 अगस्त तक आम जनता के लिए खुला रहेगा. सात अगस्त को 12वें राष्ट्रीय हथकरघा दिवस के उपलक्ष्य में किया जा रहा है. कपड़ा मंत्रालय द्वारा जारी यह महोत्सव भारत की समृद्ध और विविध हथकरघा परंपराओं का विशेष प्रदर्शन है.

समाचार विशेष

राहुल और अखिलेश सड़क पर, तेजस्वी कहां?

बिहार की राजनीति में क्यों उठ रहे हैं सवाल

पटना. दिल्ली में उबाल है. राहुल गांधी से लेकर अखिलेश यादव और यहां तक की चंद्रशेखर आजाद सुर्खियां बटोर रहे हैं. पर तेजस्वी यादव कहीं नहीं दिख रहे. यही नहीं, पटना में छात्रों पर लाठीचार्ज के बाद शुरू हुए विरोध से लेकर बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव तक कहीं भी तेजस्वी यादव नजर नहीं आ रहे. सवाल यह है कि जब कांग्रेस नेता राहुल गांधी और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव लगातार मैदान में दिख रहे हैं, तब बिहार के नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव कहां हैं?

बांकीपुर विधानसभा उपचुनाव को तो बीजेपी ने अपनी प्रतिष्ठा का चुनाव बना दिया है. मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी से लेकर बीजेपी के बड़े-बड़े नेता लगातार प्रचार कर रहे हैं. दूसरी ओर जन सुराज के संस्थापक प्रशांत किशोर खुद चुनाव प्रचार की कमान संभाले हुए हैं. मगर, महागठबंधन के सबसे बड़े नेता तेजस्वी यादव अब तक चुनाव प्रचार में ज्यादा सक्रिय नजर नहीं आए. बीजेपी इसी बात को मुद्दा बना रही है. बीजेपी का कहना है कि जब भी बड़ा राजनीतिक मुद्दा आता है, तो तेजस्वी यादव दिखाई नहीं देते.

राजद नेताओं की दलील- राजद के नेताओं की दलील अलग है. उनका कहना है कि पार्टी सिर्फ एक नेता के भरोसे नहीं चलती. राजद के विधायक और दूसरे नेता लगातार आंदोलन में शामिल हैं. उनका कहना है कि हर कार्यक्रम में तेजस्वी यादव का मौजूद रहना जरूरी नहीं है. पार्टी अपनी रणनीति के अनुसार काम करती है. सूत्रों के मुताबिक, तेजस्वी यादव इन दिनों अपनी पत्नी और बच्चों के साथ यूरोप दौरे पर हैं. मीडिया रिपोर्टों के मुताबिक, वह इस महीने की शुरुआत में विदेश गए थे. इसी वजह से वह बिहार विधानसभा के मानसून सत्र, पटना में छात्रों के आंदोलन और बांकीपुर उपचुनाव के प्रचार में अब तक शामिल नहीं हो पाए हैं.

> **पार्टी के दूसरे नेता सक्रिय : राजद**
>
> राजद नेताओं का कहना है कि यह तेजस्वी यादव का निजी दौरा है और इससे पार्टी की राजनीतिक गतिविधियों पर कोई असर नहीं पड़ेगा. उनका कहना है कि पार्टी के दूसरे नेता विधानसभा, सड़क और चुनाव प्रचार- तीनों जगह सक्रिय हैं. राजनीतिक जानकार इसे अलग-अलग नजरिए से देखते हैं. कुछ का कहना है कि जब छात्र सड़कों पर हों और विधानसभा में इतना बड़ा हंगामा हो, तब विपक्ष के सबसे बड़े नेता की मौजूदगी का अलग संदेश जाता है. बांकीपुर उपचुनाव भी आसान चुनाव नहीं माना जा रहा है. यहां बीजेपी अपनी सीट बचाने में लगी है.

उत्तराखंड में भाजपा का कुनबा बढ़ा

शामिल हुए कई राजनीतिक चेहरे

देहरादून. भाजपा प्रदेश मुख्यालय में विगत दिनों आयोजित सदस्यता ग्रहण कार्यक्रम में बड़ी संख्या में राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ताओं ने भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की. प्रदेश महामंत्री कुंदन परिहार ने सभी नए सदस्यों का पार्टी का पटका पहनाकर स्वागत किया और उन्हें प्राथमिक सदस्यता दिलाई.

इस अवसर पर कुंदन परिहार ने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र प्रथम की विचारधारा पर आधारित संगठन है. उन्होंने कहा कि राष्ट्रहित की भावना से काम करने वाले लोगों का भाजपा में हमेशा स्वागत है. नए कार्यकर्ताओं के जुड़ने से संगठन को जमीनी स्तर पर मजबूती मिलेगी और पार्टी की नीतियों को जन-जन तक पहुंचाने में मदद मिलेगी.

सदस्यता ग्रहण करने वालों में राजीव ठुकराल, पुनीत सेठी, मयंक मेहता, नितिन सेठी, पारस छाबड़ा, मोहित अरोड़ा, विवेक गंभीर, मानस अरोड़ा, सरवनजीत सिंह, गुरुदत्त सिंह, हर्षदीप सिंह और ललित कुमार सहित कई राजनीतिक एवं सामाजिक कार्यकर्ता शामिल रहे. कार्यक्रम के अंत में नए सदस्यों ने पार्टी नेतृत्व के प्रति आभार व्यक्त करते हुए संगठन को मजबूत बनाने और भाजपा की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक पहुंचाने का संकल्प लिया.

बूथ अध्यक्षों के महाकुंभ से भाजपा ने भरी हुंकार

लखनऊ. अभियान हो या संगठन की बैठक. सामाजिक कार्यक्रम हो या धार्मिक अनुष्ठान...हर मंच से भाजपा चुनावी लक्ष्य भेदने का प्रयास करती है. 2027 विधान सभा चुनाव की डगर पर रथ उतार चुकी भाजपा ने बुधवार को पहली बार प्रदेश के सभी बूथों को एक साथ मथा.

'मेरा बूथ सबसे मजबूत, बूथ जीता तो चुनाव जीता' के संकल्प को नई शक्ति देने के लिए मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य एवं ब्रजेश पाठक समेत सरकार एवं संगठन के सभी योद्धा मैदान में उतरे. संगठन की सबसे निचली इकाई संभालने वाले बूथ अध्यक्षों को मंच पर विशेष सम्मान देकर साफ कर दिया कि पार्टी बूथ मंत्र के जरिए चुनाव जीतने का लक्ष्य लेकर बढ़ेगी. इस दौरान बूथ सत्यापन कार्यक्रम भी सफल रहा. प्रदेश की 403 विधान सभा सीटों में 1918 मंडलों के बीच कुल 1,77,516 बूथ हैं. यह संगठन की सबसे निचली इकाई है जिसे पार्टी नींव का पत्थर कहती है. 11 जुलाई को प्रदेश की नई टीम की पहली बैठक में बूथ अध्यक्षों के सम्मेलन का कार्यक्रम बना.

> मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गोरखपुर में बूथ अध्यक्षों का सम्मेलन संबोधित किया, वहीं बरेली में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, शाहजहांपुर में ब्रजेश पाठक, बुलंदशहर में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी ने बूथ अध्यक्षों के चुनावी महत्व को रेखांकित किया. पार्टी ने अलग-अलग विधान सभाओं में पूर्व प्रदेश अध्यक्ष डॉ. रमापतिराम त्रिपाठी, स्वतंत्रदेव सिंह, मंत्री जेपीएस राठौर समेत सभी जनप्रतिनिधियों एवं संगठन के महारथियों को एक-एक विधान सभा में उतारा, जहां उन्होंने चुनावी रणनीति को धार देते हुए जीत के समीकरणों को भी जाना. इस बहाने पार्टी ने 2017 के सापेक्ष 2022 के चुनाव में हारी विस सीटों को फिर से जीतने की रूपरेखा बनी.

विशेष | **शहीद दिवस पर पुरानी कड़वाहट भूलकर साथ आने का खुला न्योता**

क्या माकपा के साथ आएंगी ममता बनर्जी?

कोलकाता. पश्चिम बंगाल की राजनीति में एक ऐसा ऐतिहासिक मोड़ आ गया है, जिसकी कभी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी. जिस माकपा के विरोध पर ममता बनर्जी ने अपनी पूरी राजनीति खड़ी की और जिसे सत्ता से बेदखल किया, आज उसी माकपा को उन्होंने बीजेपी के खिलाफ साथ आने का न्योता दे दिया है.

21 जुलाई शहीद दिवस के मंच से तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी ने साफ शब्दों में घोषणा की, मुझे इसमें कोई झिझक नहीं है. हम इंडिया गठबंधन के तहत साथ मिलकर आगे बढ़ेंगे. अगर आप बीजेपी से लड़ना चाहते हैं, तो हमारे साथ आएं. राजनीतिक विश्लेषक ममता बनर्जी के इस रुख को बंगाल के इतिहास में सबसे बड़ा राजनीतिक बदलाव मान रहे हैं.

ममता बनर्जी का यह बयान इसलिए सबसे ज्यादा हैरान करने वाला है, क्योंकि उन्होंने माकपा को साथ आने का यह संदेश शहीद दिवस के मंच से दिया है. 21 जुलाई का यह दिन बंगाल के इतिहास में वामपंथी शासन के खिलाफ विरोध का सबसे बड़ा प्रतीक रहा है. दरअसल, 21 जुलाई 1993 को ममता बनर्जी के नेतृत्व में युवा कांग्रेस ने राज्य सचिवालय के घेराव का आह्वान किया था. उस दौरान कोलकाता की सड़कों पर प्रदर्शन कर रहे 13 युवाओं की पुलिस फायरिंग में मौत हो गई थी. तब राज्य में माकपा के नेतृत्व वाली वाम मोर्चा सरकार ही सत्ता में थी. इसी घटना के बाद ममता बनर्जी वामपंथ के खिलाफ कभी न झुकने वाले आंदोलन का चेहरा बनी थीं. इसी आंदोलन के दम पर तृणमूल कांग्रेस साल 2011 में माकपा के 34 साल के शासन को उखाड़कर सत्ता में आई थी. तब माकपा का विरोध ही तृणमूल की जीत का मुख्य राजनीतिक नारा था.

> **दिल्ली में दोस्ती, बंगाल में कुश्ती**
>
> राजनीतिक विश्लेषकों का कहना है कि दिल्ली और बंगाल की राजनीति के समीकरण अब पूरी तरह अलग हो चुके हैं. जो पार्टियां दिल्ली में बीजेपी को चुनौती देने के लिए एक मंच पर हाथ मिला रही हैं, वे बंगाल की जमीन पर एक-दूसरे के खिलाफ आज भी कड़ी राजनीतिक प्रतिद्वंद्विता में जुटी हुई हैं. मंगलवार को इसी रुख को दोहराते हुए उन्होंने इस बात पर जोर दिया कि अगर विपक्षी ताकतों को बीजेपी से मुकाबला करना है, तो वे आपस में बंटे रहने का जोखिम नहीं उठा सकतीं.